

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 10 | अंक : 154 | गुवाहाटी | शनिवार, 30 दिसंबर, 2023 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

भारतीयों का हित हमारी सबसे बड़ी चिंता : विदेश मंत्रालय

पेज 2

ग्रेनेड विस्फोटों में शामिल सभी अल्फा-स्वा कैडर गिरफ्तार

पेज 3

मोदी ने गरीबों को दिया ताकत, प्रशस्त हुआ देश के प्रगति का मार्ग : गिरिराज सिंह

पेज 5

भारतीय फुटबॉल टीम के लिए शानदार रहा यह साल, तीन खिताब जीते...

पेज 7

असम में अब उग्रवाद का अंत!

अल्फा और केन्द्र के बीच हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता

नई दिल्ली। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (अल्फा) के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में केंद्र और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को मौजूदगी में हस्ताक्षरित समझौता, अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व वाले अल्फा गुट और सरकार के बीच 12 साल की बिना शर्त बातचीत के बाद हुआ है। इस शांति समझौते से असम में दशकों पुराने उग्रवाद के खतम होने की उम्मीद है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह मेरे लिए खुशी की बात है कि आज का दिन असम के भविष्य के लिए एक उज्वल दिन है। लंबे समय तक, असम और पूर्वोत्तर को हिंसा का सामना करना पड़ा और 2014 में पीएम मोदी के पीएम बनने के बाद, दिल्ली और पूर्वोत्तर के बीच अंतर को कम करने के प्रयास किए गए। वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि आज असम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और गृह मंत्री अमित शाह के -शेष पृष्ठ दो पर



राज्य के भविष्य के लिए सुनहरा दिन : केंद्रीय गृहमंत्री



नई दिल्ली। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (अल्फा) का तीन दशक से अधिक पुराना सशस्त्र संघर्ष खत्म हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को मौजूदगी में अल्फा के प्रतिनिधियों ने त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। अमित शाह ने इसे असम के भविष्य के लिए सुनहरा दिन करार दिया है। शाह के अनुसार अल्फा के साथ शांति समझौते के साथ ही असम में सभी सशस्त्र संघर्ष करने वाले गुट हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट आए हैं।

अमित शाह ने कहा कि शांति समझौते के बाद अल्फा के 700 सशस्त्र कैडर हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट जाएंगे। इसके पहले बोडो, आदिवासी, कार्बी और डीमासा उग्रवादी गुटों के साथ समझौता हो

अमित शाह ने कहा कि शांति समझौते के बाद अल्फा के 700 सशस्त्र कैडर हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट जाएंगे। इसके पहले बोडो, आदिवासी, कार्बी और डीमासा उग्रवादी गुटों के साथ समझौता हो

शांति समझौते का होगा शत प्रतिशत क्रियान्वयन : डॉ शर्मा

गुवाहाटी/नई दिल्ली (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (अल्फा) के साथ शुरुआत को दिल्ली में केंद्र व राज्य सरकार और अल्फा के साथ हुए शांति समझौते का राज्य में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुरुआत को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद उपस्थित समूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्फा का जन्म असम को स्वाधीन बनाने के लिए हुआ था। बाद में यह सशस्त्र संग्राम में बदल गया। इस संग्राम में 10 हजार से अधिक लोग मारे गए। मारे गए लोगों में से 95 फीसदी लोग असमिया नागरिक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के इस काले इतिहास में मरने वालों के परिजनों को यह पता नहीं था कि उनके परिवार वालों को क्यों मारा गया और मारने वालों को भी यह पता नहीं था कि आखिर क्यों मार रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिरकार अल्फा अध्यक्ष अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व में यह संग्राम समाप्त हुआ। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से आज अल्फा के साथ केंद्र व राज्य सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने कहा कि सन् 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के



-शेष पृष्ठ दो पर

पूर्वांचल केशरी
(असमिया दैनिक)
PURVANCHAL KESARI
(ASSAMESE DAILY)
GOOD LUCK PUBLICATIONS
House No. 30, D. Neog Path,
ABC, Guwahati - 781005
Mob: 94350 14771, 97070 14771

S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door
Fittings Modular Kitchen
& Accessories, etc.
D. Neog Path,
Near Dona Planet
ABC, G.S. Road,
Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात
शत्रुओं से अपने राज्य की पूर्ण रक्षा करें।
- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी
तेजपुर विवि के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने असम आएंगे रक्षामंत्री

गुवाहाटी। असम के तेजपुर स्थित तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के एक 31 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह असम आएंगे। इस दौरान रक्षामंत्री विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के बाद उन्हें संबोधित करेंगे। विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में 783 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर (पीजी) डिग्री, 428 को स्नातक (यूजी) की डिग्री, 5 को पीजी डिप्लोमा और -शेष पृष्ठ दो पर

श्लोक पोस्ट पर विवाद : सीएम ने मांगी देशभक्ति और एकता ही स्वतंत्रता का आधार : भागवत माफी, ओवैसी ने साधा निशाना

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जातिवादी टिप्पणियों वाला एक पोस्ट अपलोड किया था। जिसके बाद मामले को बढ़ता देख अब शर्मा ने माफी मांगी है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा है कि उनकी टीम ने भगवत गीता के एक श्लोक का गलत अनुवाद किया है। शर्मा ने गुरुवार रात एक्स पोस्ट हटा दी... अगर डिलीट की गई पोस्ट से किसी को और फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि वह हर सुबह



अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भगवद गीता का एक श्लोक अपलोड करते हैं, जिसमें अब तक 668 श्लोक पोस्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में मेरी टीम के एक सदस्य ने अध्याय 18 श्लोक 44 से एक श्लोक गलत अनुवाद के साथ पोस्ट किया। जैसे ही मुझे गलती का एहसास हुआ, मैंने तुरंत पोस्ट हटा दी... अगर डिलीट की गई पोस्ट से किसी को और फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि वह हर सुबह

माजुली (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ससंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने शुरुआत को कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता का आधार देशभक्ति और आपसी एकता है। इसके बिना तो स्वतंत्रता ही खरों में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने राष्ट्र को युगानुकूल स्वत्व के आधार पर विकसित करना है। संघ के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य समाज को राष्ट्रभक्त, संगठित और ओजस्वी स्वाभिमान से परिपूर्ण बनाने की दिशा में जागृत करना है। डॉ. भागवत असम के माजुली में गणवेशधारी स्वयंसेवकों के लुइत सुबनसिरी समावेश को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वयंसेवकों से सवाल किया कि क्या भारत अपनी कड़ी मेहनत से स्वतंत्रता



प्राप्त करने के बावजूद उसमें स्व या स्वत्व को बरकरार रखने में सक्षम था? डॉ. भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा स्व हमारे समय के

परिरक्षित पारंपरिक ज्ञान और दुनिया भर के सर्वोत्तम ज्ञान द्वारा समर्थित पीढ़ीगत आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विगत शताब्दियों में दुनिया को भौतिकवादी आकांक्षाओं पर आधारित दोषपूर्ण मानकों के कारण विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हमारा भारतीय मॉडल समाज को सभी पहलुओं में आत्मनिर्भर बनाने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत अपने भौतिक स्थिति के कारण हिंदुकुश पर्वत से अराकान तक बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था; इसलिए हमारे पूर्वजों को आध्यात्मिक, कलात्मक और साथ ही भौतिक रूप से विकास के चरम तक

-शेष पृष्ठ दो पर

एनएससीएन (के-वाईए) ने पूर्व विधायक की हत्या की जिम्मेदारी ली

इटानगर। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन एनएससीएन (के-वाईए) से संबंधित युंग आंग गुट ने अरुणाचल के पूर्व विधायक युमसेन माटे की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। बंदूकधारियों ने पूर्व कांग्रेस विधायक माटे की हत्या 16 दिसंबर को भारत-म्यांमार सीमा पर तिरप जिले के राहो गांव में गोली मारकर कर दी थी। उग्रवादी संगठन ने गुरुवार को एक बयान जारी करके हत्या की जिम्मेदारी ली। बयान में कहा गया कि युमसेन माटे लगातार एनएससीएन के विरोध में काम



-शेष पृष्ठ दो पर

हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की तैयारी में भारत, पाकिस्तान सरकार को भेजे दस्तावेज

नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। दरअसल, हाफिज सईद 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों सहित विभिन्न आतंकवादी हमलों के लिए वांटेड है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि आतंकवादी के प्रत्यर्पण की मांग करने वाले बागची ने कहा कि संबंधित व्यक्ति भारत में कई मामलों में वांटेड है। वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा



भेजा गया है। बागची ने अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हाल ही में प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजा गया था। मालूम हो कि सईद संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी है। हाफिज सईद को सौंपने के लिए पाकिस्तान के प्रत्यर्पण अनुरोध पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि संबंधित व्यक्ति भारत में कई मामलों में वांटेड है। वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा

मणिपुर में जेएन.1 सब-वेरिएंट का पहला मामला आया सामने

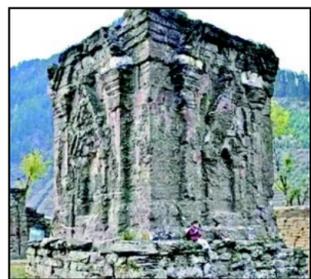
सेनापति (मणिपुर)। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल, लंबे समय के बाद मणिपुर में कोविड-19 का एक ताजा मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक, सेनापति के पाओमाटा जिले के रहने वाले एक शख्स में जेएन.1 वेरिएंट के लक्षण पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने दिल्ली से डीमापुर तक हवाई यात्रा की थी और उसके बाद सड़क मार्ग से डीमापुर से सेनापति तक यात्रा की थी। वायरस की जांच करने के लिए सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है।



-शेष पृष्ठ दो पर

पीओके में पाकिस्तानी सेना का शारदा पीठ पर कब्जा स्थानियों ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार

बेंगलुरु। पाकिस्तानी सेना के पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में शारदा मंदिर परिसर पर कब्जा किए जाने को लेकर शारदा बचाओ समिति (एसएससी) ने रोष जताया और शुरुआत को पाकिस्तान सेना के अधिकरण को हटाने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई, ताकि मंदिर के जीर्णोद्धार का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। एसएससी के संस्थापक रविंदर पंडिता ने बेंगलुरु के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने शारदा मंदिर परिसर पर कब्जा किया था और समिति के पक्ष में कोई



के आदेश के बावजूद वहां पर कॉफी होम बनाया है। उन्होंने कहा, शारदा बचाओ समिति भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तानी सेना द्वारा हाल ही में शारदा पीठ परिसर में बनाए गए कॉफी होम को हटाने और कब्जा करने का मुद्दा उठाने का अनुरोध किया। यह तीन जनवरी, 2023 को पीओके के सुप्रीम कोर्ट को ऐतिहासिक आदेश के बावजूद है, जिसमें शारदा बचाओ समिति के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। उन्होंने कहा कि पीओके में नागरिक समाज ने भी इस मुद्दे और बाउंड्री वॉल को हटाने का मुद्दा उठाने के बारे में एसएससी के साथ

-शेष पृष्ठ दो पर

अनुच्छेद 370 पर एससी के फैसले को संघवाद के नजरिए से नहीं देखा जा सकता : जस्टिस कौल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संघवाद के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के कुछ वर्गों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की। बता दें कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था, जिसे (अनुच्छेद 370) ने 2019 में निरस्त किया था। कुछ अलग तरह से किया गया। सरकार ने संविधान के दायरे में रहकर, सरकारी आदेश



थी। जस्टिस संजय किशन कौल ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, मेरा मानना है कि कश्मीर से जुड़े फैसले को संघवाद के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में जो हुआ है उसे दोहराया जाना है या कहीं और दोहराया जा सकता है। जस्टिस कौल ने कहा कि इसका कारण यही है कि कश्मीर का भारत में विलय

-शेष पृष्ठ दो पर

संपादकीया

राम मंदिर सिर्फ सियासी नहीं

अयोध्या का राम मंदिर सांस्कृतिक पुनरोत्थान का एक उदाहरण है, तो राजनीति का भी मुद्दा है। 1989 से 2019 तक के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्रों में भाजपा इसे शामिल करती रही है। एक राजनीतिक दल सांस्कृतिक विकास और बदलाव की बातें नहीं करता, क्योंकि वे चुनावी मुद्दे नहीं आँके जाते। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, इस एक मुद्दे ने भाजपा को 2 सांसदों से 303 सांसदों तक की अप्रत्याशित छलांग लगाने की ताकत दी है। अन्य मुद्दों की भी भूमिकाएँ रही हैं, लेकिन राम मंदिर के उद्घोष पर जो उन्माद और धुरवीकरण, भाजपा के पक्ष में, पैदा होता रहा है, उससे राजनीतिक लक्ष्य भी साधे गए हैं। आस्थाएँ कई और मुद्दों के प्रति भी हो सकती हैं। आस्थाएँ अयोध्या, काशी और मथुरा तक ही सीमित क्यों हैं? भाजपा और संघ परिवार के छाया-चेहरे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, इस एक मुद्दे ने भाजपा को 2 सांसदों से 303 सांसदों तक की अप्रत्याशित छलांग लगाने की ताकत दी है। अन्य मुद्दों की भी भूमिकाएँ रही हैं, लेकिन राम मंदिर के उद्घोष पर जो उन्माद और धुरवीकरण, भाजपा के पक्ष में, पैदा होता रहा है, उससे राजनीतिक लक्ष्य भी साधे गए हैं। आस्थाएँ कई और मुद्दों के प्रति भी हो सकती हैं। आस्थाएँ अयोध्या, काशी और मथुरा तक ही सीमित क्यों हैं? भाजपा और संघ परिवार के छाया-चेहरे ही अदालतों में इन मुद्दों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। भाजपा माने अथवा न माने, राम मंदिर 2024 के आम चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा साबित होगा, लेकिन फिर भी राम मंदिर समारोह को पूरी तरह सियासी करार नहीं दिया जा सकता। गांव-गांव, घर-घर जाना, प्रभु राम की तस्वीर के साथ प्रसाद बांटना और अयोध्या में दर्शन करने आने के आमंत्रण और इन गतिविधियों के लिए संघ परिवार के स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को झूटी पर लगाने के अभिप्राय क्या है? जाहिर है कि रामत्व के जरिए हिंदुत्व के प्रसार का भी राजनीतिक लक्ष्य है। यह भाजपा का प्राचुर-तंत्र भी है। यदि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविस्मृतस्वरानंद सरस्वती कहते हैं कि चुनावी फायदे के लिए भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के एक ही हिस्से का उद्घाटन करवा रही है, भगवान राम की बाल्य प्रतिक्रमा की प्राण-प्रतिष्ठा चुनाव के मद्देनजर कई जा रही है, तो उन्होंने पूर्णतः गलत नहीं कहा है। शंकराचार्य को कांग्रेस और भाजपा में बांट कर नहीं देखा जा सकता। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने एक ही धर्म के राजनीतिकरण के कारण राम मंदिर समारोह का बहिष्कार किया है। पार्टी ने इसे 'संविधान-विरोधी' करार दिया है, क्योंकि संविधान में 'धर्मनिरपेक्ष भारत' की बात कही गई है। हम इस दलील को नहीं मानते। वैसे भी वामपंथी दल वैचारिक और मानसिक स्तर पर चीन के ज्यादा करीब रहे हैं। उन्होंने भारत-चीन युद्ध के दौरान भी देश का साथ नहीं दिया था। बहरहाल लोकतंत्र में राजनीति को खारिज नहीं किया जा सकता। राजनीति से आम आदमी भी जुड़ा है। यदि भगवान राम के दर्शनार्थ अथवा नया, भव्य मंदिर देखने देश भर से भक्तगण उमड़ते हैं, अयोध्या में भक्ति और भजन की तरंगें प्रवाहित होती हैं, यदि विरोधी राजनीति के नेतागण भी अपने 'आराध्य' के लिए अयोध्या मंदिर में जुटते हैं, तो उसे महज 'राजनीति' भी न कहा जाए। भक्ति, अध्यात्म, दर्शन, आस्था और राजनीति की परिभाषाएँ भिन्न हैं। बेशक राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा का राजनीतिक विस्तार हुआ है। अन्य धर्मावलंबी, संप्रदाय, मत के लोग और समाज भी समारोह मनाते हैं। प्रधानमंत्री अपने आवास पर ईसाइयों को आमंत्रित करते हैं, ताकि ईसा मसीह की जयंती का समारोह मनाया जा सके। प्रधानमंत्री 'सिख साहबजादे' के बलिदान पर 'वीर बाल दिवस' आयोजन में भी शिरकत करते हैं। प्रधानमंत्री को हमने मखिजद में भी देखा है। प्रधानमंत्री एक भक्त, आराध्य के तौर पर 'हिंदू' भी, हैं, लिहाजा सिर्फ मोदी-विरोधी सियासत के कारण राम मंदिर पर सवाल उठाना अथवा उसे 'सांप्रदायिक' करार देना तार्किक नहीं है। जिस तरह 1990 के दशक में अयोध्या की आड़ में राजनीति की गई, इस बार उस राजनीति से बचना चाहिए।

कुछ

अलग

तीस मार से पचास मार खां

वह उनके करीब कहीं नहीं रहे, लेकिन सदा सबको ही बताना उन्हें अच्छा लगता है कि वे उससे पूछ कर ही पानी पीते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा कहने से उनके आसपास धमाके होने लगते हैं और रहगुजर बहुत श्रद्धा से उन्हें देख कर कहते हैं, 'देखिए यही वह सज्जन हैं जिनसे पूछ कर वे पानी पीते हैं।' अचानक कई दिनों से वह इस नगरी में चले आए थे। वह आरामपसंद लोगों की एक ऐसी नगरी थी, जहां कुछ तीसमार खां और बहुत से भुक्खड़ लोग रहते थे। बात भुक्खड़ों की पहले कर लो, क्योंकि पूरी उम्र हाडतोड़ मेहनत करने के बाद भी इनकी कोई पूछ-प्रतीत नहीं होती। दिन-रात खेतों में काम किया। महामारी को अपने बदन पर सहने की परवाह किए बगैर, बंजर धरती के छोटे-छोटे टुकड़ों को ऊसर बना दिया। लहलहाती फसलें खड़ी कर दीं। उनके आसरां को इन फसलों से भर दिया। चश्माधारी विशेषज्ञों ने बताया कि अरे यही तो वे लोग हैं, जिनकी भरपूर मेहनत ने इस मारक रोग का एक कारण भुखमरी नहीं बनने दिया। रोग पीड़ितों को अकाल पीड़ित होने से बचाया। अब इन लोगों की क्या बात करें, सहिब? ये वही लोग हैं जो हमेशा बेहतर जिंदगी की कतार से टूट गए लगते हैं। आजकल आखिरी आदमी भी उन्हें कहना बंद कर दिया गया है। ऐसा होना ही था, क्योंकि जबसे ऐसे लोगों के कल्याण के लिए अन्त्योदय योजनाओं के बैनर सजने लगे, उसके अलम्बरदार अपनी-अपनी कतार के आखिरी आदमियों के झुण्ड को लेकर चले आए, कि जिनमें राहत अनुदान के पहले कौर से लेकर आखिरी कौर तक बंट गया, और दशकों से इन कतारों में खड़े आखिरी लोग, अब और जगह नहीं है, और नौकरी नहीं, और राशन नहीं है, की नियति झेलने लगे। इस नियति के बावजूद बहुत दूर-दूर तक फैले हुए हैं। कभी सुना था इस देश में, इस नगरी में कोई

भी बिना काम नहीं रहने दिया जाएगा। कम से कम परिवार के एक सदस्य को वर्ष में सौ दिन काम अवश्य मिलेगा, जिससे लोगों को काम से कम अन्न के चन्द दाने अपने पेट में डालने में दिक्कत न हो। दुर्दिनों का प्रकोप बढ़ा तो यह संख्या डेढ़ सौ दिन कर दी गई। सुना है आजकल खजाने की भायं-भायं बढने के कारण यह फिर सौ दिन हो गई है। जो मनरेगा का अड कहलाते थे, वे कहते के किन आखिरी लोगों में बंट गए, कुछ खबर नहीं, क्योंकि इधर इधर कतार से छिटक गए लोगों की कतार और भी लम्बी हो गई। और इस देश की बहुत सी नगरियों के अलम्बरदार इन योजनाओं की पूर्णतः धरके नहीं। ऐसी राहत और अनुदान घोषणाओं के कितने कारनामे आपको और सुना दें? कारनामे सुनाने वाले इन कल्याणकारी मसीहाओं की कमी नहीं। चुनावों के करीब आने की जब आहट होने लगती है तो ऐसे ही अलम्बरदार आपके शहरों में प्रगट हो जाते हैं, जो अपने आपको शहर के तीसमार खां लोगों के अंतरंग चोबदार बताते हैं। समझा देते हैं कि वह तो पानी भी पूछ कर उनसे पीते हैं। इसलिए कभी भी आपको हथेली पर सरसों जमाने जैसा कोई कठिन काम करवाना हो, तो उन्हें अवश्य याद कर लें, पलक झपकते ही आपका काम हो जाएगा, और तीस मार खां का कुनवा बढ कर पचास सौ मार खां हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें इन लम्बी कतारों से निकाल दिए गए लोगों को आज भी समझ नहीं आई कि अगर तीस मार खां और उनके चोबदारों द्वारा घोषित स्वर्णयुग वास्तव में ही उनकी निर्वासित धरा पर आ गया है, तो दुनिया भर के भ्रष्टाचारी देशों के सूचकांकों में उनके देश के भ्रष्टाचारी होने का रूतबा और कैसे बढ गया? रिश्ततखोरों का यह देश तो शुरू से ही कहलाता था, अब यह रिश्ततखोरी जीने का एक ऐसा अनिवार्य ढंग कैसे बन गई।

विकास सक्सेना

लोकसभा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन के नेता फिलहाल एक-दूसरे के खिलाफ ही षडयंत्र रचने में जुटे हैं। सामान्य तौर पर राजनीति में भिन्नधात कुशल रणनीति माना जाता है, लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल दलों के नेता इस सामान्य परम्परा का भी पालन करने को तैयार नहीं हैं। वे खुले मंचों से एक-दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों के निशाने पर सबसे ज्यादा कांग्रेस और उसके नेता हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव जिस तरह कांग्रेस की नीतियों और नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, उससे राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि विपक्षी गठबंधन के ये नेता भाजपा को हराने के लिए एकजुट हुए हैं या फिर उनका उद्देश्य कांग्रेस को खत्म करना है। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को विपक्षी गठबंधन का सबसे मजबूत साथी माना जा रहा था क्योंकि ये पहले से यूपीए की हिस्सा थे लेकिन इंडी गठबंधन में चर्चा के बिना ही इन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की लोकसभा की सीटों का आपस में बांट कर अपनी मंशा साफ कर दी है। बिहार की लोकसभा की कुल 40 सीटों में से राजद और जदयू ने 17-17 सीटें आपस में बांट ली हैं। बाकी बची छह सीटें कांग्रेस और वामपंथी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में जदयू भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल थीं और उसने अपने हिस्से की 17 सीटों पर प्रत्याशी उतार कर 16 पर जीत हासिल की थी। इसलिए जदयू 17 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब यह देखना काफी रोचक होगा कि क्या कांग्रेस और वामपंथी दल महज छह सीटें पाकर संतुष्ट रह पाएंगे। राजद और जदयू ने जिस तरह बिहार की लोकसभा सीटों को आपस में बांट लिया इसे कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल विपक्षी गठबंधन की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नाम का प्रस्ताव रख दिया। उनके प्रस्ताव का अरविन्द केजरीवाल ने सपथन कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे दलित समाज से आते हैं इसलिए कोई भी

दृष्टि

कोण

यूपी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर हो रहे हैं सकारात्मक प्रयास

देश के सबसे बड़े राज्य में यूपी जोड़ो यात्रा को जो अपार जनसमर्थन मिल रहा है, उससे ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि यूपी में कांग्रेस पिछले 34 सालों से सत्ता से बाहर है। गठबंधन की राजनीति से उसकी कम्पट चुकी है, जिसके चलते वह केंद्र में भी मजबूती से नहीं जम पा रही है। बदलते दौर में यूपी कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर पर सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम जल्द ही सामने आएंगे। कहना न होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हावर का सूबाई गठबंधन नीति से यूपी समेत हिंदी पट्टी के जमे-जमाये नेताओं ने पार्टी के कार्यक्रमों से जो किनारा करना शुरू किया, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के दस वर्षीय कार्यकाल को यदि छोड़ दिया जाए तो पुराना मिलसिला अब जाकर धमने के आसार प्रबल हुए हैं। वहीं, यूपी में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एंडी-चौटी की कमान दी जाएगी। वजह स्पष्ट है कि यदि कांग्रेस को प्रदेश में मजबूत बनाना है तो हमें राष्ट्रीय नीति के साथ-साथ क्षेत्रीय नीति और स्थानीय नेता विकसित करके उनमें तारतम्य



बिठाने की समुचित पहल करनी होगी। वहीं, विभिन्न कार्यक्रमों के सहारे लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी। खास बात यह कि हमें राजनीतिक प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ देने में नए-पुराने के तफरके में संतुलन बिठाना होगा। साथ ही नेतृत्वगत अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना होगा और चरणबद्ध रूप से जिम्मेदारी तय करनी होगी, ताकि पार्टी संगठन में जान फूँकी जा सके। ऐसा ही इसलिए कह रहा हूँ कि गत दिनों लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में हमारे नेता राहुल गांधी यूपी कांग्रेस के

नेताओं से नाखुश दिखे। जैसी की मीडिया रिपोर्ट आई है। बताया गया है कि यूपी में पार्टी के अंदर उत्साहित नेताओं की कमी है। यूपी कांग्रेस के नेता केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से ना तो वहां पार्टी खड़ी हो पा रही है और ना ही जीत मिल रही है, जबकि तेलंगाना के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से पार्टी खड़ी कर ली और चुनाव भी जीत लिया। वहां चार नेता ऐसे थे जो सीएम बनना चाहते थे, इसलिए सबसे मेहनत की और सबकी मेहनत से पार्टी जीती। वहीं, यूपी में ऐसे तीन नेता नहीं हैं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हों और उसे पूरा करने के लिए कुछ कर गुजरने का माद्दा रखते हों। एक अन्य टिप्पणी पर गौर करें तो पता चला है कि पार्टी का हर सदस्य चाहता है कि गांधी परिवार के सदस्य यूपी में पार्टी के अधिपति का नेतृत्व करें, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे राज्य में कितने सक्रिय होंगे। यह ठीक है कि मुगलमान इस चुनाव में कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा और उन सीटों को

अपने गठबंधन में सपा से लाना होगा। जबकि कुछ लोगों ने सोचा कि वे बसपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं, जबकि बसपा के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। इस दौरान कई अलग-अलग मुद्दे सामने आए, लेकिन सभी की राय थी कि पार्टी को कड़ी सौदेबाजी करनी चाहिए और न केवल सम्मानजनक हिस्सेदारी बल्कि मजबूत सीटें भी हासिल करनी चाहिए। ऐसे में सीधा सवाल है कि जब प्रदेश में पार्टी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है और अपने नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एक नई टीम बनकर आगे बढ़ रही है। तो फिर हमें पिछले 34 साल की उपलब्धियों-अनुपलब्धियों पर भी एक सरसरी नजर डाल लेनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में अपने सबसे खराब दौर में भी पार्टी ने कई प्रयोग किए। अकेले चुनाव भी लड़ी और गठबंधन का साथ भी लिया। लेकिन कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सकी, आखिर ऐसा क्यों? यह यथ पर है। बहरहाल, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने नए अध्यक्ष अजय राय के हाथ में कमान सौंपने के बाद यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज कर चुकी है।

देश

दुनिया से

डाकिए का झोला भारी, झोली खाली

डाक कर्मचारी जिस झोले में चिट्ठियां रखकर डाक बांटने जाते हैं, वह काफी भारी है, लेकिन उनकी झोली खाली है। झोला भारी होने से मतलब यह है कि उनके पास काम काफी ज्यादा है, लेकिन झोली खाली है क्योंकि वेतन कम मिलता है। कम से कम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डाक कर्मियों की यही हालत है। भारत में किसी समय सरकारी क्षेत्र को बेहतरीन रोजगार प्रदाता सेवा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन जैसे-जैसे केंद्र एवं राज्य सरकारों का बजट बढ़ रहा है और सरकारी सेवाओं का बजट बढ़ रहा है और सरकारी सेवाओं में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सरकारी रोजगार के नाम पर कच्ची नौकरियां देकर औने-पौने तन्ख्याहों पर अपने कर्मचारियों के जायज हक न देकर उनका शोषण करती नजर आ रही हैं। यही वजह है कि सेवा शर्तों में तमाम विसंगतियों और खामियों को लेकर भारत में इन दिनों जहां सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं तो कुछ-कुछ इन्हीं की तर्ज पर अपनी सेवा शर्तों में सुधार, पक्की नौकरी, वेतन बढ़ोतरी और पेंशन की गारंटी के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले ग्रामीण डाक सेवक संघघर्षरत हैं। पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में डाक कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण डाकघर की सेवाएं गड़बड़ गई थीं। डाकघरों में चुंबापा, अंगुठा पेंशन सहित कई कार्यों को निपटाने के लिए लोग पहुंचते हैं। कई लोगों के महत्वपूर्ण चिट्ठी-पत्र और नौकरी, इंटरन्यूजपों सहित पारसलों भी डाक से आते हैं। जाहिर है कि डाक कार्यालयों को असुविधा तो हुई ही होगी। लेकिन इसी विभाग में सेवारत डाक सेवकों की सेवा शर्तों और वेतन-भत्तों का यदि मानवीय दृष्टिकोण से जायजा लें तो लगता है कि केंद्र सरकार विगत कई दशकों से डाक सेवकों की सेवाओं का न केवल जमकर दुरुपयोग कर रही है, बल्कि शोषण करने के मामले में भी सबसे आगे है। आज महंगाई के जमाने में अच्छे वेतन की आस सभी को रहती है। डाक सेवकों में बाहर्बर्ब पास से लेकर स्नातकोतर उपाधि धारक युवा अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निर्धारित 3 घंटों के बजाय 8-9 घंटों तक सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन बदले में जिंदा रहने के लिए उन्हें कच्ची नौकरी और मामूली वेतन मिल रहा है। चिट्ठीयों से लेकर ई-पोस्ट तक के सफर को पूरा करते-करते लगभग 500 साल पुरानी भारतीय डाक

प्रणाली आज दुनिया की सबसे विश्वसनीय और बेहतरीन डाक प्रणाली में अखल स्थान पर ही है। भारत में 155015 पोस्ट ऑफिस (डाकघर) हैं। कई उतार-चढ़ावों से गुजरते कई सौ साल पहले जब आजकल की तरह खत पहुंचाने के संसाधन और व्यवस्था नहीं थी, तब कबूतरों द्वारा खत एक से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे, अथवा घुड़सवारों के जरिए खत पहुंचाए जाते थे। भारत में डाक सेवा की व्यवस्था साल 1766 में स्थापित की गई और भारत में पहला डाकघर 1786 में मद्रास में स्थापित किया गया। 1877 में पारसल सेवा, 1879 में पोस्ट कार्ड, 1880 में मन आर्डर और 1911 में इलाहाबाद से पहली एयरमेल सेवा शुरू की गई। इसी तरह 1935 में पहला इंडियन पोस्टल आर्डर शुरू हुआ। 1972 में पिन कोड की शुरुआत, 1986 में स्पीडपोस्ट का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में औसतन एक भारतीय पोस्ट ऑफिस सात हजार से ज्यादा लोगों को सेवाएं देता है। ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण डाक सेवक ही डाक संकलन, दूरस्थ क्षेत्रों (बीट) में डाक वितरण सहित कार्यालय कार्य, पैशन और वेतन-भत्तों में सुधार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी, लेकिन सामान्य नागरिकों को होने वाली असुविधा के दृष्टिगत अपनी हड़ताल वापस ले ली। अब यह केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह भी न्याय की मांग और ग्रामीण डाक सेवकों की जायज मांगों को शीघ्र पूरा करे, ताकि वे कर्मचारी भी सम्मानजनक तरीके से अपने परिवारों की देखभाल कर सकें। ग्रामीण डाक सेवकों की प्रमुख मांगें हैं कि भारत सरकार उन्हें पक्की नौकरी, आठ घंटे काम, इसी के अनुसार वेतन और पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान करे। नियमित कर्मचारियों के समान पहली जनवरी 2016 से समग्र संबंधित निरंतरता भत्ता मिले, 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तर्कसंगत निर्धारण, वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए वेजेज वृद्धि, समयबद्ध वित्तीय उन्नयन सहित कमलेश चंद्र समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों को लागू किया जाए। समूह बीमा कवरण को पांच लाख तक बढ़ाया जाए।

पुलिस की अपनी अदालत

अपनी तरह के मार्गदर्शक फैसले ने आपराधिक जांच के दायरे से हिमाचल के पुलिस मुख्या और कांगड़ा की एसपी से उनका वर्तमान किरदार छीन लिया। माननीय हाईकोर्ट ने पालमपुर के व्यापारी की अरदास को सुनते-हुए राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं कि जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए पुलिस महकमे के ओहदेदार परिदृश्य से हटाए जाएँ। ऐसे कड़े निर्देश की वजह समझें तो यह कानून व्यवस्था के आलम में हिमाचल की शर्मिंदगी है। जिन परिस्थितियों में पालमपुर के व्यापारी को पुलिस से वास्ता पड़ा, उससे द्वितीयक मामले में सारी कानून व्यवस्था का तामझाम तार-तार हुआ है। कारोबारी निशांत के अपने निजी मसले, व्यापारिक क्लेश या कानूनी पेचीदगियाँ हो सकते हैं और उनके निपटारे के लिए अदालती प्रक्रिया और न्याय प्रणाली की अहम भूमिका सुनिश्चित है, लेकिन यहाँ यह व्यक्ति पुलिस प्रणाली के खौफ के सामने अपनी लाचारी-मजबूती का निज़र करता हुआ गुहार लगा रहा है कि उसे नाहक डराया-धमकाया जा रहा है। वह शिमला और कांगड़ा पुलिस के प्रमुखों से अपनी शिकायत दंग करवाता है। आश्चर्य यह कि एक ही राज्य में शिमला के एसपी और कांगड़ा की एसपी के बीच कानून की दृष्टि, एफ आई आर की पाटी और कांस्टाबल बदल जाता है। आश्चर्य यह कि डीजीपी स्तर का टॉप ब्रास अधिकारी एक व्यवसायी को पंद्रह बार क्यों मिस्रड काल दे रहा है या उसके मातहत पालमपुर के अधिकारी क्यों निशांत पर दबाव डालकर संवाद करवाना चाहते हैं। क्या पुलिस की अदालतें अब राज्य की अपनी कानून व्यवस्था का दिशा परिवर्तन है। हम यह नहीं कहते कि निशांत का माजरा क्या है और इस मामले की परतें कितनी भोली, ईमानदार या वीधत्स हैं, फिर भी यह कतई नहीं मान सकते कि पुलिस महकमे का आला अधिकारी अपने प्रभाव को अदालत बनाकर, अदालत के बाहर खुद अदालत बन जाए। कांगड़ा पुलिस मुख्या के रूप में एसपी महोदया ने कानूनी प्रक्रिया के आधारभूत ज्ञान को क्यों गिरवी रखा और किसके इशारे पर अपनी भूमिका के उज्वल पक्ष को गौण कर दिया, यह संशय पैदा करता है। जाहिर तौर पर हाईकोर्ट के सख्त निर्देश का बचाव सेवकों से सख्त होना पड़ेगा। यह एक मामला नहीं, बल्कि राज्य की पुलिस मशीनरी का हुलिया है और चारित्रिक गिरावट भी है। यह सुशासन की लोकतांत्रिक आस्था के बिलकुल विपरीत राज्य का अंधा और बहरापन है। अगर सुख्ख सरकार व्यापारी की प्राथमिक शिकायत पर ही कार्यवाई करती तो अदालत के लिए संदेह प्रकट करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ हम पुलिस महकमे से इतर भी व्यवस्था को नाको चने चवाने पर मजबूर करने वाले कई अन्य विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्न खड़ा लगाना चाहेंगे। यह राज्य अब भोला नहीं, बल्कि ऐसी मिली भागत का पर्याय है जहाँ चंद नेता, अधिकारी, नौकरशाह, मीडिया के लोग, ठेकेदार व कर्मचारी संघटनों के ओहदेदार व्यवस्था को अपने स्वार्थी इरादों की वसीहत में बंदल रहे हैं। हिमाचल में भ्रशासनिक, राजनीतिक व सामाजिक भ्रष्टाचार से एक अजीब सा नाता विकसित हो रहा है, जो विकास की अग्रिम पंक्ति पर निजी तौर पर वांछित उच्चारण पा रहा है।



सिधिया बोले-आयोध्या में हवाई अड्डे के उद्घाटन का दिन ऐतिहासिक

नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिधिया ने कहा कि आयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन देश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा और दूसरे चरण में इसके समग्र क्षेत्र बड़ाकर और रनवे को लंबाई बढ़ाकर इसका बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जो 6,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बना है। सिधिया ने दिए साक्षात्कार में कहा कि आयोध्या हवाई अड्डे से संपर्क आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। उन्होंने कहा, देश भर में नागरिक उड्डयन क्षमता के विकास की जरूरत है और विशेष रूप से आयोध्या के लिए यह काफी अहम है क्योंकि यह धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से हमारे दिलों में जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार, हवाई अड्डा परियोजना का दूसरा चरण 6,500 वर्ग मीटर की सुविधा से 50,000 वर्ग मीटर तक विकास करने से जुड़ा है। उन्होंने कहा, हम रनवे का विस्तार 3,750 मीटर तक कर रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पर्याप्त है। आयोध्या हवाई अड्डे का पहला चरण 1,450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6,500 वर्ग मीटर है और यह सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा कर सकता है। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री की ओर से आयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा न केवल नागरिक उड्डयन के लिए, न केवल आयोध्या शहर के लिए, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, न केवल भारत के लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है जो हिंदू धर्म के प्रति हमारी आत्माओं की जीवंतता और प्रतिबद्धता में विश्वास करते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि आयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आयोध्या धाम रखा जाएगा और इस संबंध में एक अधिसूचना जल्द ही जारी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि हवाई अड्डे से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि विमानन नियामक डीजीसीए से 14 दिसंबर को एयरोड्रम लाइसेंस प्राप्त करने वाले हवाई अड्डे का रनवे 2,200 मीटर लंबा है और यह दिन और रात के संचालन के साथ-साथ 550 मीटर से अधिक की कम दूरीता की स्थिति के लिए भी उपयुक्त है। टर्मिनल भवन का अगला हिस्सा श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है। टर्मिनल भवन के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला, चित्रों और भित्ति चित्रों से सजाया गया है। आयोध्या हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम, एलईडी लाइटिंग, वर्षा जल संचयन, फव्वारे के साथ भूमिर्माण, जल उपचार संयंत्र, सोलर उपचार संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र जैसी विभिन्न स्थिरता सुविधाओं से लैस है।

न्यूज ब्रीफ

उदय-कोटक ने 30 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी प्लान शेयर किया: वित्त मंत्री सीतारामण ने कहा- धन्यवाद, कोटक बोले-भारत के बचतकर्ता अब इन्वेस्टर्स में बदले

नई दिल्ली। कोटक महिंद्रा बैंक के फांडर उदय कोटक ने साल 2047 तक भारत की जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विचार शेयर किए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उदय कोटक ने कहा- भारत के ड्रीम के लिए एक फाइनेंशियल सेक्टर मॉडल: 9 प्रतिशत पुनःअवलोकन, 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी भारत बचतकर्ताओं से निवेशकों के देश में बदल रहा है। 80 के दशक की शुरुआत में, भारतीय बचतकर्ताओं को सोने और जमीन की तुलना में फाइनेंशियल एसेट पर कम भरसा था। धीरे-धीरे बचतकर्ता ने कुछ हिस्सा बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और एलआईसी में भूत कर दिया। 90 के दशक में, इंडिटी निवेश को सद्ग माना जाता था। इसलिए पुंजी की तलाश में कंपनियां विदेशी संस्थागत निवेशक के पास गईं। संभावना देखी और कंपनियों में खरीदारी की, जबकि भारतीय बचतकर्ता दूर रहे। कंपनियों ने कम पीपुलर लवजमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पुंजी जुटाई। हालांकि, 2000 के दशक की शुरुआत में चीजें बदलनी शुरू हुईं। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बाजारों में भारतीय बचतकर्ताओं की रुचि में सुधार हुआ। वह बचतकर्ता अब निवेश का आनंद ले रहा है। म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, कैश इंडिटी और डेरिवेटिव मार्केट, इंडिया फंड, भारत में ग्लोबल प्राइवेट इंडिटी, जैसे अन्य प्लेटफॉर्म, इंडिटी के लिए लोअर टैक्स रिजीम, सभी ने एक बचतकर्ता को एक निवेशक में बदल दिया है। 1.कोविड के बाद कई निवेशक जुड़े। उन्होंने मुख्य रूप से अपसाइड देखा है। हालांकि वर्तमान में स्थिति तुलनीय नहीं है, हमें 80 के दशक के जापान को अपने दिमाग में रखना होगा। इसका निष्कर्ष इंडेक्स पीक 1989 में था। 34 साल बाद लगभग शून्य व्याज दरों के साथ, निष्कर्ष अभी भी 1989 के अपने शिखर से नीचे है। हमें पीएलसी, रेगुलेशन और एजुकेशन से बुनबुले से बनना चाहिए। कंपनियों को प्रोडक्टिव यूज के लिए कैपिटल की लोअर कॉस्ट पर इंडिटी जुटानी चाहिए। हमें डेट में टैक्स आर्बिट्रिज को प्रोत्साहित, जब तक डेट मार्केट नहीं बढ़ता यह एक पैर वाली दौड़ होगी। डेट और इंडिटी के बीच हाइएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट पर 39 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का मौजूदा अंतर शायद बहुत बड़ा है। डिविडेंड्स पर डबल टैक्सेशन पर पुनर्विचार की जरूरत है। एक शेयरहोल्डर एक पार्टनर की तरह होता है। जब पार्टनरशिप से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसा मूव किया जाता है तो कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगता है। यही प्रिंसिपल शेयरहोल्डर्स पर भी लागू होता है। डेरिवेटिव्स के माध्यम से लो कॉस्ट लेवरेज फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे-जैसे बचतकर्ता निवेशक बनते हैं, बैंकिंग क्षेत्र को अपनी जमा राशि और फंड की कॉस्ट पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को सार्थक रूप से पुंजी बाजार (डेट और इंडिटी) की ओर जाना होगा और बैंकों से दूर जाना होगा। बैंक स्टोरेज हाउसेज के बजाय कॉर्पोरेट डेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाएंगे।

एफआइयू ने नौ विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया, यूआरएल को भी ब्लाक करने की सिफारिश

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआइयू) ने मनी लाँड्रिंग कानून का उल्लंघन करने के आरोप में नौ विदेशी क्रिप्टोकॉरेसी और वर्युअल डिजिटल एसेट (वीडीए) प्लेटफॉर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इनके यूआरएल को ब्लाक करने की सिफारिश की है। एफआइयू ने इस संबंध में मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। इन वीडिए पर मनी लाँड्रिंग के साथ आतंकवाद के लिए फंडिंग का आरोप है। एफआइयू के मुताबिक जिन वीडिए को ब्लाक करने की सिफारिश की गई है उनमें रिवटजरलैंड की बिनासे, सिगापूर की कुकायन व मिक्स ग्लोबल, हांगकांग की हुओबी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की क्रकेन व बिटफिनेक्स, कैमैन आइलैंड की गेटड्राइवआईओ, अमेरिका की बिटरेक्स, लवजमबर्ग की बिटसैटप शामिल हैं। एफआइयू के निदेशक ने इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा है कि ये वीडिए अवैध तरीके से मनी लाँड्रिंग कानून का उल्लंघन करते हुए काम कर रहे हैं। धरुल और विदेशी वीडिए मुख्य रूप से वर्युअल डिजिटल एसेट के लेन-देन का काम करते हैं और इस प्रकार का काम करने के लिए इन्हें भारत के एफआइयू के यहां अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है। अभी 31 वीडिए एफआइयू के साथ पंजीकृत हैं। हालांकि ऐसी आशंका है कि कई वीडिए बिना पंजीयन के काम कर रहे हैं।

नए साल में 20,000 रुपए में करें विदेश यात्रा : 4 देशों ने वीजा फ्री एंट्री शुरू की

नई दिल्ली। थाईलैंड, मलेशिया, ईरान और श्रीलंका ने हाल ही में इंडियन ट्रेवलर्स के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया है। इससे इन देशों की यात्रा करना आसान हो गया है। ईरान को छोड़कर अन्य तीन देशों की ट्रिप 20-22 हजार रुपए के बजट में की जा सकती है। यदि आप टोटल ट्रेवल कॉस्ट देखें, तो एक्सपेंसेस के मुख्य रूप से तीन एलिमेंट्स हैं: ट्रांसपोर्टेशन, अकांमोडेशन, फूड एंड बेवरेज। यदि आप इन खर्चों को कम कर दें, तो ट्रेवल करना सस्ता हो जाएगा। इसलिए, अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको सस्ते फ्लाइट टिकट से लेकर होटल बुक करने के तरीके और कैंसी एक्सचेंज करने जैसी जरूरी चीजों के बारे में बता रहे हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी ट्रिप को खुद प्लान कर सकते हैं।



वीजा फ्री एंट्री का मतलब है कि आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बजट यात्रा जरूर कर सकेंगे। इसी तरह अगर आप फ्लाइट से मलेशिया के शहर लंकावी की यात्रा करना चाहते हैं तो, भोपाल से लंकावी की राउंड ट्रिप का खर्च करीब 40,000 हजार रुपए आएगा। वहीं अगर आप विशाखापट्टनम जैसे शहर के जरिए कुआलालंपुर पहुंचते हैं और वहां से ट्रेन, बस और शिप या डोमेस्टिक फ्लाइट की मदद से लंकावी पहुंचते हैं तो राउंड ट्रिप का खर्च करीब 17,000 रुपए आएगा। यानी, करीब-करीब 23 हजार रुपए की बचत हो जाएगी।

सस्ती फ्लाइट टिकट बुकिंग के तरीके:

जितनी जल्दी हो सके फ्लाइट बुक करें - ट्रेवल क्लॉगर वरुण चागिश के अनुसार आपको अपनी फ्लाइट ट्रेवल डेट के 2-3 महीने पहले से टिकटों की मॉनिटरिंग शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही आपको सस्ती फ्लाइट मिलें, टिकट बुक कर लें। बजट फ्लाइट पाने में यह तरीका काफी कारगर है।

उड़ान भरने के लिए सबसे सस्ती जगह खोजें - यदि आप फ्लाइट के लिए खुद को किसी खास डेस्टिनेशन तक सीमित नहीं रखते हैं तो सस्ती फ्लाइट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसे एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए, आप भोपाल में रहते हैं और मलेशिया के शहर कुआलालंपुर की यात्रा करना चाहते हैं। अगर आप भोपाल से कुआलालंपुर की टिकट बुक कराएंगे तो राउंड ट्रिप यानी, आने-जाने का खर्च करीब 28,000 हजार रुपए आएगा। वहीं अगर आप भोपाल की जगह विशाखापट्टनम जैसे शहर से टिकट बुक करते हैं तो ये आपको करीब 12,000 रुपए में मिल जाएगा। भोपाल-विशाखापट्टनम की राउंड ट्रिप ट्रेन से कर सकते हैं। स्लीपर क्लास में इसके लिए 1200-1500 रुपए खर्च होंगे। यानी, कुल करीब 13,500 रुपए लगेंगे। इससे 15,000 रुपए की बचत होगी। यह तरीका आराम

स्काईस्कैनर जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल करें -

स्काईस्कैनर जैसी वेबसाइट आपको सस्ती टिकट खोजने में मदद करती है। मान लीजिए, आपको भोपाल से कुआलालंपुर जाना है। ऐसे में वेबसाइट पर आप भोपाल से कुआलालंपुर की टिकट सर्च करने के बजाय भारत से मलेशिया डालें और ट्रेवल डेट के बजाय ट्रेवल मंथ चुनें। ये वेबसाइट आपको भारत के जिस भी शहर से मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चोपेस्ट शहर और मंथ का पता चलने के बाद आप चाहें तो एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर भी इस इश्यूशन का टिकट बुक करा सकते हैं।

ब्राउजर में प्राइवेट मोड का इस्तेमाल करें - फ्लाइट टिकट बुक करते समय हमेशा प्राइवेट मोड का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, गूगल क्रोम में इनकांमिटो मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट कुकीज का इस्तेमाल करती है और

ब्राउजर पर की गई सर्च के हिसाब से किराया बढ़ा देती है। बड़ती कीमतें दिखाकर वे आपको मनोवैज्ञानिक रूप से महंगे टिकट बुक करने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट प्राइवेट मोड के इस्तेमाल की सलाह देते हैं।

वीकडेज पर टिकट बुक करें - यह कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन आम तौर पर वीकडेज पर किराया महंगा होता है। इसलिए अपनी फ्लाइट टिकट हमेशा वीकडेज में बुक करें। ऐसे में इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स से टिकट बुक कराने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है।

लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें - किसी दूसरे देश में पहुंचने के बाद अगर आप प्राइवेट टैक्सी से ट्रेवल करते हैं तो ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है। इसलिए, वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे बस, डोमेस्टिक फ्लाइट, ट्रेन का इस्तेमाल करना सस्ता पड़ेगा। आप अपने प्लान के अनुसार दूसरे देश पहुंचने से पहले से ही वहां के एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं।

रहने के लिए सस्ती जगह के से बुक करवाएं - रहने के लिए मुख्य तौर पर तीन ऑप्शन उपलब्ध हैं। होस्टल, होटल और लोकल लोगों के साथ स्टे। जहां आप लोकल के साथ फ्री में रुक सकते हैं, तो वहीं होस्टल में रहना भी होटल की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है। इसकी बुकिंग आप बिना पैसे दिए पहले से ही करवा सकते हैं। सस्ता होस्टल बुक करने के लिए आप बुकिंग डॉट कम जैसी वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। यहां आप रेंटिंग और रेट के हिसाब से होस्टल चुन सकते हैं। कुआलालंपुर जैसे शहरों में 500-800 रुपए पर नाइट के हिसाब से आपको होस्टल मिल सकता है। अगर आप होस्टल में नहीं रहना चाहते हैं तो रेंटिंग और रेट के हिसाब से होटल की भी बुकिंग कर सकते हैं। लोकल लोगों के साथ फ्री में रहने के लिए आप काउचसर्फिंग जैसी वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। काउचसर्फिंग पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। इस वेबसाइट पर कई सारे होस्ट होते हैं जो ट्रेवलर्स को होस्ट करते हैं। लोकल के साथ रुकने का एक फायदा यह भी है कि वो आपको बेहतर तरीके से शहर घुमा सकते हैं। उनके साथ लोकल फूड भी ट्राय कर सकते हैं।

एसबीआई समेत तीन बैंकों में पैसा सबसे सुरक्षित आरबीआई ने वित्तीय प्रणाली के लिहाज से बताया

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत देश में तीन ऐसे बैंक हैं, जिनमें आपका पैसा सबसे सुरक्षित है। ये तीनों ऐसे बैंक हैं, जो डूब नहीं सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का कहना है कि एसबीआई के अलावा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक घरेलू वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक बने हुए हैं। देश में वित्तीय प्रणाली के स्तर पर ये इतने बड़े बैंक हैं कि डूब नहीं सकते। आरबीआई को अगस्त, 2015 से हर साल इसी महीने में वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंकों के नामों की जानकारी देनी पड़ती है। केंद्रीय बैंक ने कहा, आईसीआईसीआई बैंक पिछले साल की तरह ही श्रेणी आधारित संरचना में बना हुआ है। वहीं, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक उच्च श्रेणी में चले गए हैं। नियमों के अनुसार, ऐसे संस्थानों को प्रणाली के स्तर पर महत्व के आधार पर चार श्रेणियों में रखा जा सकता है। बैंकों की श्रेणी में हुआ बदलाव एसबीआई श्रेणी तीन से श्रेणी चार में और एचडीएफसी बैंक श्रेणी एक से श्रेणी दो में स्थानांतरित हो गया। घरेलू स्तर पर व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी) को लेकर एक अप्रैल, 2025 से एसबीआई के लिए अधिभार 0.8 फीसदी होगा। वहीं, एचडीएफसी बैंक के लिए 0.4 फीसदी होगा।



आधारित संरचना में बना हुआ है। वहीं, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक उच्च श्रेणी में चले गए हैं। नियमों के अनुसार, ऐसे संस्थानों को प्रणाली के स्तर पर महत्व के आधार पर चार श्रेणियों में रखा जा सकता है। बैंकों की श्रेणी में हुआ बदलाव एसबीआई श्रेणी तीन से श्रेणी चार में और एचडीएफसी बैंक श्रेणी एक से श्रेणी दो में स्थानांतरित हो गया। घरेलू स्तर पर व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी) को लेकर एक अप्रैल, 2025 से एसबीआई के लिए अधिभार 0.8 फीसदी होगा। वहीं, एचडीएफसी बैंक के लिए 0.4 फीसदी होगा।

2023 के आखिरी कारोबारी दिन बाजार कमजोर संसेक्स 138 अंक टूटा, निफ्टी 21750 के नीचे

नई दिल्ली। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच इंपॉजिस, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों के दबाव में भारतीय शेयर बाजार 2023 के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ खुले। सुबह करीब 9.20 बजे बीएसई सेंसेक्स 201 अंक या 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72,208 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 61 अंकों या 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 21,717 पर कारोबार कर रहा था।



सांख्यिक संकेतों के बीच इंपॉजिस, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों के दबाव में भारतीय शेयर बाजार 2023 के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ खुले। सुबह करीब 9.20 बजे बीएसई सेंसेक्स 201 अंक या 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72,208 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 61 अंकों या 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 21,717 पर कारोबार कर रहा था।

कमजोर होने से रुपया लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मजबूत हुआ और छह पैसे की बढ़त के साथ 83.14 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि मुद्रा कारोबारियों के अनुसार शेयर बाजार की कमजोर धारणा और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से रुपये में तेजी का रुख प्रभावित हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 83.14 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और 83.12 से 83.16 रुपये प्रति डॉलर के दायरे में कारोबार करता दिखा। इसके बाद स्थानीय इकाई ने डॉलर के मुकाबले 83.14 पर कारोबार किया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 6 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपये में लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की मजबूती के साथ 83.20 के स्तर पर बंद हुआ था।

मोदी सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल में टैक्स कलेक्शन तीन गुना हुआ, अब 2024 में तथा होगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में व्यक्तिगत आय और कॉर्पोरेट कर संग्रह तीन गुना बढ़कर 19 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। लोगों की आय पर रिफंड के समावोजन के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ रुपये हो गया। चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर - व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट कर - से संग्रह में अब तक 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस गति से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में लगभग 19 लाख करोड़ रुपये के अनुमान से अधिक होगा। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार कम दरों और कम छूट के साथ कर व्यवस्था को सरल बनाने की कोशिश कर रही है। 2019 में, सरकार ने छूट छोड़ने वाले कॉर्पोरेट्स के लिए कर की कम दर की पेशकश की। इसी तरह की योजना अप्रैल 2020 में आम लोगों के लिए भी पेश की गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कर स्लैब को युक्तिसंगत

नेतृत्व वाली सरकार 2014 में सत्ता में आई थी। शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के भागीदार (प्रत्यक्ष कर) गौरी पुरी ने कहा कि कर प्रशासन के डिजिटलीकरण और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने पर निरंतर ध्यान देने से उच्च कर अनुपालन दरों में योगदान मिला है। 2024 के लिए उम्मीद यह होगी कि सरकार कर निश्चितता बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष कर प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना जारी रखे। प्रत्यक्ष कर संग्रह में चालू वित्त वर्ष में अब तक 20 फीसदी इजाफा होने और हर महीने जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि होने से 2024 में भी देश की अर्थव्यवस्था के सकारात्मक रूप से बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मासिक वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2023-24 में औसत सकल मासिक जीएसटी संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद को इस साल हुई बैठकों में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने पर स्पष्टीकरण दिया गया। परिषद ने दो बैठकों के दौरान यह स्पष्ट करने का फैसला

नेतृत्व वाली सरकार 2014 में सत्ता में आई थी। शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के भागीदार (प्रत्यक्ष कर) गौरी पुरी ने कहा कि कर प्रशासन के डिजिटलीकरण और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने पर निरंतर ध्यान देने से उच्च कर अनुपालन दरों में योगदान मिला है। 2024 के लिए उम्मीद यह होगी कि सरकार कर निश्चितता बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष कर प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना जारी रखे। प्रत्यक्ष कर संग्रह में चालू वित्त वर्ष में अब तक 20 फीसदी इजाफा होने और हर महीने जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि होने से 2024 में भी देश की अर्थव्यवस्था के सकारात्मक रूप से बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मासिक वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2023-24 में औसत सकल मासिक जीएसटी संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद को इस साल हुई बैठकों में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने पर स्पष्टीकरण दिया गया। परिषद ने दो बैठकों के दौरान यह स्पष्ट करने का फैसला



किया कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में प्रवेश के समय लगाई गई पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। इसके अलावा, परिषद ने सभी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य बनाने का फैसला किया। जीएसटी अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कथित जीएसटी चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 71 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इनमें से कई कंपनियों ने इस मांग पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया है। इंडसर्वा के पार्टनर (अप्रत्यक्ष कर) शशि मैथ्यूज ने कहा कि कर की उच्चता दर लगाए जाने से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में तेजी से वृद्धि रुक गई है। उन्होंने कहा, यह उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस उद्योग की परेशानियों पर विचार करेगी। इनमें से कुछ मुद्दे अदालतों के समक्ष लंबित भी हैं और अदालतों से निर्णयों के रूप में भी कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। कुल मिलाकर, 2024 में इन मुद्दों पर एक सकारात्मक हल निकलता हितधारकों के लिए फायदेमंद होगा।

आँरी के सारे दावों को श्रुति हासन ने बताया फर्जी, कहा-

कौन है वो मैं नहीं जानती

श्रुति हासन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म प्रभास स्टार सालार से सुर्खियां बटोर रही हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इन सबके बीच अब श्रुति ने उन्हें असभ्य

कहने के लिए ओरी उर्फ ओरहान अवत्रामणि पर पलटवार किया है। एक इंटरव्यू में श्रुति ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आँरी कौन हैं। उन्होंने कहा कि वह लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करती हैं, जैसा लोग उनके साथ करते हैं। इस दौरान श्रुति ने अपनी शादी को लेकर चल रही अफवाहों पर भी खुलकर बात की। अनजान लोगों के लिए, आँरी ने सालार एक्ट्रेस को असभ्य व्यक्ति कहा था। सोशल मीडिया बर्डी ने हाल ही में रेटिड पर एक एएमए में दावा किया कि जब वे एक-दूसरे से मिले तो श्रुति ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए श्रुति ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह (आँरी) कौन हैं। मैं अपना काम करने और अपनी जिंदगी जीने में व्यस्त

हूँ। मैंने हमेशा उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है जो मेरे जीवन और मेरे आस-पास अच्छी ऊर्जा लाते हैं। मैंने हमेशा यह कहा है और मैं इस पर कायम हूँ। मैं एक दर्पण की तरह हूँ, मैं लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती हूँ जैसा मेरे साथ किया जाता है और मुझे इसका कभी अफसोस नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह बहुत बचकाना है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे नहीं जानते वे मेरे बारे में बात न करें। मैंने अपनी जिंदगी पूरी खुलेपन और ईमानदारी से जी है। अगर मैं शादीशुदा होता तो मैं इसे क्यों छिपाता? मैंने एक स्पष्टीकरण पोस्ट किया क्योंकि मेरा सोशल मीडिया इस खबर से स्पेम हो गया था... यह हास्यास्पद था। मैं इस पर हंस रही थी।

स्किपिंग रोप एक्सरसाइज करते समय कुछ गलतियों से बचना है जरूरी



फिटनेस प्रीक लोग फिट रहने के लिए तरह-तरह की एक्सरसाइज करते हैं। आमतौर पर लोगों को ऐसी फिटनेस रूटीन फॉलो किए जाने की सलाह दी जाती है। जिसे फॉलो करने में खुद को भी मजा आए। हालांकि हर व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से फिटनेस रूटीन फॉलो करता है। किसी को योग करना पसंद होता है तो कोई कार्डियो करता है। लेकिन आपको बता दें कि स्किपिंग रोप या रस्सी कूदना एक ऐसा वर्कआउट है। जो लगभग हर किसी को पसंद आता है। हम सभी लोगों में से कई लोग ऐसे हैं, जो बचपन में रस्सी कूदा करते थे। हालांकि बचपन का यह खेल फिटनेस का एक हिस्सा है। यह खुद को फिट रखने का एक अच्छा तरीका है। भले ही रस्सी कूदना एक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इसे सही तरीके से करना काफी जरूरी होता है। लोग रस्सी कूदने के लिए दौरान काफी छोटी-छोटी गलतियां करते हैं। ऐसे में इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताते जा रहे हैं कि रस्सी कूदने के दौरान किन गलतियों को करने से बचना चाहिए।

अधिक हाथ हिलाना: ज्यादातर लोग रस्सी कूदने के दौरान हाथों को ज्यादा हिलाते हैं। खासतौर पर बिगनर रस्सी कूदने के दौरान अपने हाथों, कोहनी या कंधे को अधिक मूव कर सकते हैं। लेकिन बता दें कि यह अप्रभावी होने के साथ ही थका देने वाला है। इसलिए प्रयास करें कि आइने के सामने खड़े होकर रस्सी कूदें, जिससे आपको अपने शरीर की मूवमेंट को मॉनिटर करने का मौका मिले। इससे आप आसानी से बाँड़ी मूवमेंट को मॉनिटर कर पाएंगे। रस्सी कूदने के दौरान आपके आर्म स्थित होने चाहिए। वहीं कलाइयों से

ज्यादा मूवमेंट होनी चाहिए।

अधिक ऊंचा कूदना: बहुत से लोग ज्यादा ऊंचा कूदते हैं, अमूमन यह लगती सभी लोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। क्योंकि जब आप ज्यादा ऊंचा कूदते हैं, तो आपके बार-बार अटकने की संभावना होती है। साथ ही आपके पैरों पर भी अधिक जोर पड़ता है और आप जल्दी थक जाते हैं। इसलिए रस्सी कूदने के दौरान आपको जमीन से सिर्फ 1-2 इंच ऊपर ही कूदना चाहिए। ऊंचाई आपके घुटनों तक नहीं आनी चाहिए।

वार्मअप ना करना: किसी भी वर्कआउट को करने से पहले वार्मअप किया जाना बेहद जरूरी होता है। इसलिए रस्सी कूदने के दौरान भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग समय बचाने के चक्कर में अच्छे से वार्मअप नहीं करते हैं। वहीं सही तरह से वार्मअप नहीं किए जाने पर रस्सी कूदने से आपको चोट लगने की अधिक संभावना होती है। इसलिए इसे करने से पहले आपको जॉगिंग या फिर जॉगिंग जैक आदि कुछ मिनट के लिए करना चाहिए।

एडवांस मूव्स: आपको बता दें कि स्किपिंग रोप एक्सरसाइज में भी कई वैरिएशन होते हैं। लेकिन प्रैक्टिस और लेवल को ध्यान में रखते हुए यह वैरिएशन किए जा सकते हैं। लेकिन कई बिगनर दूसरों की देखा-देखी में क्रॉसओवर या डबल अंडर मूव्स करने लगते हैं। लेकिन बिगनर होने पर इन मूव्स को करने से आपको चोट लगने का अधिक खतरा होता है। इसलिए इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

ईशा कोप्पिकर ने टिमी नारंग से 14 साल बाद लिया तलाक

अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर शादी के 14 साल बाद पति टिमी नारंग से अलग हो गई हैं। दोनों पिछले कुछ समय से चल रहे अनुकूलता संबंधी मुद्दों के कारण अलग हो गए हैं। जब उन्होंने मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की, तो ऐसा लगा जैसे बात नहीं बनी। माना जाता है कि ईशा कुछ समय पहले अपनी बेटी के साथ घर से बाहर चली गई थीं। फिलहाल दोनों अपनी प्राइवेट को सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसलिए इस बारे में बात नहीं करना चाहते। ईशा कोप्पिकर की शादी खटाई में पड़ती नजर आ रही है। एक्टर अपने होटल व्यवसायी पति टिमी नारंग से अलग हो गए हैं। जब ई-टाइम्स ने डॉन अभिनेता से संपर्क किया, तो उन्होंने



एक टेक्स्ट संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि मुझे कुछ नहीं कहना है। इसे बहुत जल्दी है। मुझे अपनी निजता चाहिए। मैं आपकी संवेदनशीलता की सराहना करूंगा। ईशा ने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया है और वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी फिल्म उद्योगों का भी हिस्सा थीं। 2000 में फिल्म 'फिजा' से बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने कंपनी (2002), कांटे (2002), पिंजर (2003), डॉन जैसी फिल्मों में काम किया। और डरना मना है सहित अन्य। वह अगली बार तमिल फिल्म अयलान में नजर आएंगी।



A unique initiative upholding the right to live with dignity of aging parents and dependent divyang siblings

Assam Employees' PRANAM Act

(The Assam Employees' Parent Responsibility and Norms for Accountability and Monitoring Act, 2017)

Salient features

- All employees working under the State Government / Government undertakings / State PSUs come under the purview of this Act
- Three-tier structure with time-bound procedure to deliver timely justice
- If any parent or divyang sibling of the Government employee is financially neglected, compensation up to 10% (and in exceptional cases up to 15%) can be claimed by them from the monthly salary of the employee concerned
- If a government employee dies before retirement, his/her dependent and financially neglected parents and divyang siblings can claim compensation upto 10% (and in exceptional cases up to 15%) from the Compassionate Pension received by the spouse/legal heir. However this is not applicable in the case of Family Pension
- If the designated authority or appropriate authority has, without any reasonable cause, refused to receive an application or has not disposed of the application within the time-limit, PRANAM Commission will impose a penalty of Rs. 100 per day

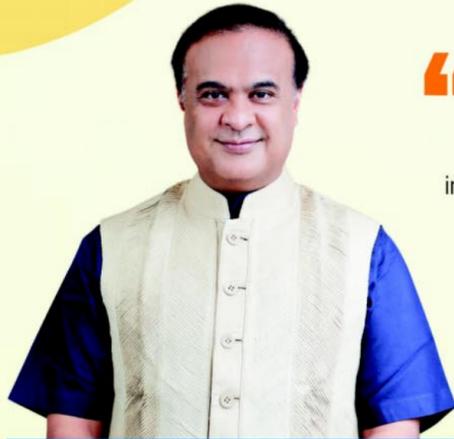
Procedure for seeking compensation

- Aggrieved parents/divyang siblings need to submit their application to the Drawing and Disbursing Officer (DDO), who is the designated authority of the employee concerned. The DDO is empowered to determine the eligibility of the claim and is bound to dispose of the case within 90 days
- In case the DDO fails to dispose of the case within the time limit or if the employee, parent or divyang sibling is aggrieved by the order of the designated authority, appeal may be preferred to the 1st Appellate Authority, the Commissioner & Secretary, GAD, Assam Secretariat, Dispur
- In case the Commissioner & Secretary, GAD fails to dispose of the case within 60 days or if any of the parties concerned is aggrieved by the order, the appeal may be preferred to the PRANAM Commission
- The PRANAM Commission will dispose of the appeal within 90 days and the decision of Commission will be final and binding

“

We are very proud that Assam is the first state in the country to implement the PRANAM Act which is an effort to protect elderly parents and divyang siblings of Government employees in their times of need

”



Dr Himanta Biswa Sarma
Chief Minister, Assam



Issued in Public Interest by :

PRANAM COMMISSION

GAD Building, Panbazar, Guwahati-781001
Ph-0361-2730515 (Chief Commissioner) & 84740-93342 (Registrar)
Website : <https://pranam.assam.gov.in>

Published by Directorate of Information & Public Relations, Assam

Connect with us



@diprassam dipr.assam.gov.in

Subscribe to Asom Barta



Whatsapp 'Assam' at 8287912158

-- Janasanyog /D/15507/ 23